

प्रेषक,

डॉ० उमाकांत पंवार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निबन्धक,
सहकारी समितियाँ, उत्तराखण्ड।

सहकारिता, गन्ना एवं चीनी अनुभाग:-1

देहरादून, दिनांक ०९ जनवरी, 2013

विषय:- जनपद ऊधमसिंहनगर में एकीकृत सहकारी विकास परियोजना के लिये वित्तीय वर्ष 2013-14 में वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या:-5344/नियो०/आई०सी०डी०पी०-ऊधमसिंहनगर/2013-14 दिनांक 09 दिसम्बर, 2013 तथा वित्त विभाग के आदेश संख्या- 284/XXVII-1/2013, दिनांक 30 मार्च 2013 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि एकीकृत सहकारी विकास परियोजना, ऊधमसिंहनगर के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2013-14 में तृतीय किस्त के रूप में देय धनराशि के सापेक्ष ₹1,89,13,000/- (रुपये एक करोड़ नवासी लाख तेरह हजार मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर रखे जाने हेतु श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। उक्त धनराशि की शत प्रतिशत प्रतिपूर्ति राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा राज्य सरकार को की जाएगी तथा उक्त धनराशि आवश्यकतानुसार निबन्धक, सहकारी समितियाँ, उत्तराखण्ड द्वारा निर्दिष्ट कार्य में व्यय करने हेतु सम्बन्धित परियोजना को उपलब्ध करायी जायेगी। यह स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन है:-

- (1) स्वीकृत धनराशि के उपयोग की मदवार/लक्ष्यवार अद्यतन वित्तीय भौतिक प्रगति से शासन को त्रैमासिक रूप से अवगत कराया जायेगा।
- (2) स्वीकृत धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार किया जायेगा और यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इस योजना के अन्तर्गत अब तक स्वीकृत ऋणों की प्रतिपूर्ति हो चुकी है और उसे कोषागार के सम्बन्धित लेखाशीर्षक में जमा करा दिया गया है।
- (3) स्वीकृत अंशपूजी, ऋण एवं अनुदान की धनराशि, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा मूल रूप में स्वीकृत परियोजना में उल्लिखित शर्तों/मदों/लक्ष्यों के अनुसार व्यय की जायेगी।
- (4) स्वीकृत धनराशि, निगम की परियोजना के अनुरूप राज्य सरकार द्वारा वर्तमान में व समय समय पर निर्गत शर्तों के अनुरूप नियंत्रित होगी।
- (5) इन शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित किये जाने की पूर्ण जिम्मेदारी निबन्धक, सहकारी समितियाँ उत्तराखण्ड की होगी।
- (6) आवश्यक उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं इसकी सूचना यथासमय राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को तथा राज्य सरकार को त्रैमासिक रूप से उपलब्ध कराना होगा और पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित होने के उपरान्त ही अवशेष धनराशि के उपयोग की कार्यवाही की जानी होगी।
- (7) परियोजना हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का समयबद्ध आधार पर उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा।

2. पैरा-1 में स्वीकृत धनराशि किसी अन्य प्रयोजन के लिये प्रयोग में नहीं लाई जायेगी। परियोजना का नियमानुसार लेखा परीक्षण किया जायेगा तथा महालेखाकार, उत्तराखण्ड द्वारा भी लेखापरीक्षण किया जा सकता है।

3. उपर्युक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2013-14 के आय व्ययक में सहकारिता विभाग के सम्बन्धित अनुदान संख्या-18 के अन्तर्गत निम्नलिखित शीर्षकों के नामे डाला जायेगा-

लेखाशीर्षक	वर्तमान स्वीकृति
2425- सहकारिता-आयोजनागत 00-800-अन्य व्यय 04-एकीकृत सहकारी विकास परियोजना हेतु अनुदान (राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा पोषित) 00-20-सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	4518
4425- सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत 00-200-अन्य निवेश 03-समितियों की अंशपूंजी में विनियोजन (राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम) 00-30-निवेश/ऋण	6898
6425-सहकारिता के लिए कर्ज-आयोजनागत 00-800-अन्य कर्ज 04-एकीकृत सहकारी विकास योजना के अन्तर्गत ऋण (राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा पोषित) 00- 30-निवेश/ऋण	7497
योग-	18913

(रूपये एक करोड़ नवासी लाख तेरह हजार मात्र)

4. ये आदेश वित्त विभाग के आदेश संख्या-284/XXVII-1/2013, दिनांक 30 मार्च, 2013 द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक-आई०डी० मूल में।

भवदीय,

(डॉ० उमाकांत पंवार)
सचिव।

2081

संख्या:- (1)/XIV-1/2013, तददिनांकित।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, ओबराय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून, उत्तराखण्ड।
2. वित्त-4/नियोजन/भाषा अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. प्रबन्ध निदेशक, एन०सी०डी०सी०, 4-सीरी इन्स्टीट्यूशनल एरिया, हौज खास, नई दिल्ली को अवमुक्त धनराशि की राज्य सरकार को प्रतिपूर्ति किए जाने सम्बन्धी अनुरोध के साथ प्रेषित।
4. मण्डलायुक्त, कुमायूं मण्डल, उत्तराखण्ड।
5. जिलाधिकारी, ऊधमसिंह नगर, उत्तराखण्ड।
6. जिला सहायक निबन्धक, सहकारी समितियां, ऊधमसिंहनगर।
7. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, अल्मोड़ा, उत्तराखण्ड।
8. बजट निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. प्रभारी, एन०आई०सी०, सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. प्रभारी, मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(यू०सी० कबडवाल)
अपर सचिव।